

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-1067/2013

श्रीमती विजय तंवर

—अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर, बीकानेर।
2. अति. निदेशक (प्रशासक) चिकित्सा एवं स्वा. सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 31.01.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अति. निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक—नर्सिंग/2001/SPL/40 दिनांक 11.12.2001 के अनुसार अपीलार्थिया की नियुक्ति नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भूखरेड़ी जिला चुरू में समेकित वेतन रु. 4500/- अक्षरे रूपये चार हजार पांच सौ मात्र पर हुई। अपीलार्थिया ने उपरोक्त पद पर दिनांक 22.12.2001 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थिया वर्तमान में प्राथ. स्वा. केन्द्र सुरनाना तह. लूणकरणसर जिला बीकानेर में कार्यरत है। प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 22.12.2001 से अपीलार्थिया की सरकारी सेवा अनवरत रही है, यानि की सरकारी सेवा में एक दिन का भी व्यवधान नहीं रहा। नियुक्ति तिथि से आज तक समान पद पर कार्यरत है। चयनित वेतनमान हेतु सरकारी कर्मचारी की अंतिम सात वर्ष की सेवा संतोषजनक होनी चाहिए जबकि अपीलार्थिया की तो समस्त 12 वर्षीय सरकारी सेवा स्वच्छ, सराहनीय, उत्कृष्ट श्रेणी की रही है। अतः प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर अपीलार्थिया प्रथम चयनित वेतनमान दिनांक 22.12.2010 से प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:—
“(i) यह है कि अपील अपीलार्थिनी स्वीकार फरमायी जावे तथा प्रत्यर्थीगण के निर्देशित कर पाबंद किया जावे कि अपीलार्थिनी की सेवा की गणना प्रथम

नियुक्ति तिथि 11.12.2001 से कर प्रथम 9 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जावे तथा उक्त दिनांक 11.12.2001 से ही अपीलार्थिनी के पक्ष में Pay and Seniority Protection का लाभ प्रदान करने का आदेश फरमाया जावे।

(ii) यह है कि अन्य अनुतोष जो हक अपीलार्थिनी हो तथा माननीय अधिकरण जिसे उचित एवं मुनासिब समझे अता फरमाया जावे।”

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थिया को प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11-12-2001 के द्वारा अर्जेन्ट टेम्परेरी बेसिस पर नर्स श्रेणी-I के पद पर छह माह के लिये 4500/- रुपये प्रतिमाह वेतन फिक्स एमाउण्ट पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी। राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2008 के अन्तर्गत नर्स श्रेणी-II के पद पर चयनित होने पर निदेशालय जयपुर के आदेश दिनांक 8-8-09 के द्वारा चयनित अभ्यार्थियों की चयन सूची जारी की गयी, जिसमें अपीलार्थिया द्वारा दर्शाया गया है कि इस सूची में उसका नाम क्रम सं. 180 पर अंकित है। ग्रामीण नर्स श्रेणी-II पद पर चयन होने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के आदेश दिनांक 13-8-09 के द्वारा अपीलार्थिया का पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लूणकरणसर बीकानेर के अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजासर भाटियान में दो साल के परिवीक्षाकाल पर वेतन श्रृंखला 9300-34800 में किया गया है। लेखाविज्ञ 2010 माह जनवरी के बिन्दु सं. 3 के अनुसार संवर्ग में नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही 9. 18 व 27 वर्ष की सेवा की गणना करते हुए चयनित वेतनमान देय है।
4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 11.12.2001 से अपीलार्थी की सेवा की गणना करते हुए अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत चयनित वेतनमान का लाभ स्वीकृत किया जाये। इसके विरुद्ध प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि जो नियुक्ति दिनांक 11.12.2001 को दी गई थी, वह तदर्थ अस्थायी आधार पर दी गई थी। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्ति थी। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-2008 के अंतर्गत नर्स श्रेणी-द्वितीय के पद पर चयनित होने पर निदेशालय के आदेश दिनांक 08.08.2009 के द्वारा दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.08.2009 से ही मानी जा सकती है और इसी दिनांक से अपीलार्थी की सेवा

की गणना करते हुए उसे चयनित वेतनमान देय है। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की जो प्रथम नियुक्ति की दिनांक 11.12.2001 के आदेश के द्वारा हुई थी, वह संविदा नियुक्ति दी गई थी। उक्त नियुक्ति आदेश दिनांक 11.12.2001 (अनुलग्नक-1) में यह भी अंकित है कि अपीलार्थी की नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध पूर्णतः संविदा के तहत की गई है। इस प्रकार अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 11.12.2001 के पश्चात दी गई हैं, वह नियमों के तहत नियमित नियुक्ति होना नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम-2008 के अंतर्गत नर्स श्रेणी-द्वितीय के पद पर चयनित होने पर निदेशालय के आदेश दिनांक 08.08.2009 के द्वारा दी गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति आदेश दिनांक 08.08.2009 के पश्चात से ही मानी जा सकती है।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है:-

- "(a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
 (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
 (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
 (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
 (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate

authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

7. हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी की जो नियमित नियुक्ति हुई है, वो आदेश दिनांक 08.08.2009 के पश्चात सेवा की ग्रहण करने की दिनांक से हुई है। इससे पूर्व की सेवाएं संविदाकर्मों के रूप में दी गई थी, जिसे नियमित सेवा होना नहीं माना सकता। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त दृष्टांत में यह माना गया है कि नियमितिकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। यह भी माना है कि वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में नियमितिकरण की दो भिन्न तारीखें नहीं हो सकती। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की जो सेवाएं स्क्रीनिंग के बाद नियमित की गयी है, उससे पूर्व की सेवा को अपीलार्थी वरिष्ठता एवं अन्य लाभों के लिये अपनी सेवा में नहीं जुड़वा सकता है।
8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)